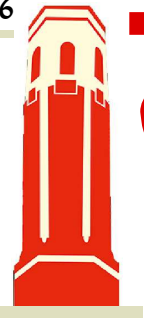


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 265
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

महिला मंत्री ने लगाई सुरक्षा की गुहार

◆ रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला किसी आम महिला का नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो जारी कर अपने पति गिरधारी लाल साहू से जान का खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत किए जाने की बात भी सामने रखी है। वीडियो जारी होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी ने इस प्रकरण को और गंभीर बना दिया है।

मामले ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला सुरक्षा, घरेलू संबंधों में उत्पन्न विवाद और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि



◆ पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री
◆ थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने से बढ़ी गंभीरता

और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी आवश्यक है। ऐसे में आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण होगी। सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्य ने देहरादून के कैट थाने में शिकायत देकर

अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कथित रूप से अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही, एक कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग का उल्लेख करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं।

इन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, क्या प्राथमिकी दर्ज की गई है और कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच किस स्तर पर है। इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। मंत्री की सुरक्षा से जुड़े किसी भी खतरे को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि रेखा आर्य स्वयं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। उनके विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण तथा अधिकारों से जुड़े विषयों से भी संबंधित है। ऐसे में उनके द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताना स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा का विषय बनेगा।

विपक्ष के लिए यह मामला सरकार को घेरने का मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार से पूछ सकते हैं

कि जब प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री को ही अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? हालांकि, किसी एक मामले के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायत की गंभीरता सरकार और पुलिस की जवाबदेही अवश्य बढ़ाती है।

इस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली पद पर पहुंचने वाली महिलाओं को अक्सर राजनीतिक विरोध, सामाजिक अपेक्षाओं और निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी महिला की सुरक्षा का सवाल उसके पद, प्रतिष्ठा या राजनीतिक प्रभाव से तय नहीं होना चाहिए। यदि मंत्री ने वास्तव में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया है, तो उनकी शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई

►► शेष पृष्ठ 7 पर

कैबिनेट मंत्री के आरोपों पर पति का पलटवार

फर्जी तहरीर वापस लो, भ्रष्टाचार की भी जांच कराओ: साहू

हमारे संवाददाता

देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। रेखा आर्य की ओर से पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए देहरादून में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई के बाद अब गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। गाड़ी में बैठकर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में साहू ने रेखा आर्य की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें चुनौती दी है कि वे अपनी शिकायत और बयान वापस लें। साथ ही उन्होंने रेखा आर्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।

गिरधारी लाल साहू का यह वीडियो आज सामने आया है, जबकि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और पुलिस कार्रवाई

को लेकर मामला पहले ही चर्चा में है। अब साहू के सार्वजनिक रूप से सामने आकर जवाब देने से दोनों के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। एक ओर रेखा आर्य ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, तो दूसरी ओर साहू ने आरोपों को गलत बताते हुए अपनी बात सार्वजनिक की है।

वीडियो में गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्य को संबोधित करते हुए कहा कि जिस ऑडियो को सामने लाया गया है, वह उनके अनुसार ऑटोफिशियल इंटरलिंग्वेज (एआई) की मदद से बनाया गया है और इसका उद्देश्य उनका घर तोड़ना है। उन्होंने रेखा आर्य पर सत्ता और पद का अहंकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और हमेशा कोई एक व्यक्ति ताकत में नहीं रहता।

साहू ने कहा कि रेखा आर्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने उनके



राजनीतिक जीवन में किस तरह सहयोग किया। उन्होंने अपने संबोधन में दावा

किया कि उन्होंने रेखा आर्य को शुरुआती दौर से आगे बढ़ाने और राजनीतिक रूप

से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि आज वही उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, जबकि उन्होंने उनके लिए लंबे समय तक काम किया है। गिरधारी लाल साहू ने वीडियो में रेखा आर्य से अपनी शिकायत और बयान पर दोबारा विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं और रेखा आर्य को ईश्वर को साक्षी मानकर यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी उनके साथ उत्पीड़न किया, गाली-गलौज की या भ्रष्टाचार से जुड़ी रकम ली। साहू ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा रेखा आर्य को भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बच्चों के राशन और उनके हिस्से के पैसे में कटौती नहीं करने के लिए कहते रहे। उनके मुताबिक, उन्होंने रेखा आर्य को लगातार गलत कामों से बचने की सलाह दी, लेकिन अब उन्होंने पर आरोप लगाए जा रहे हैं।

दून वैली मेल

संपादकीय

अब एसएसआर की दस्तक

लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल नामों का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का आधार है। इसमें दर्ज एक नाम किसी नागरिक की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि नाम कटने से वह अपने सबसे बुनियादी अधिकार से वंचित हो सकता है। इसलिए मतदाता सूची में सुधार की हर प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की कसौटी पर परखी जानी चाहिए। लेकिन जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने हों और इसी बीच विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी एसएसआर की दस्तक हो, तो सवाल केवल चुनावी प्रक्रिया का नहीं रह जाता। सवाल यह भी है कि मतदाता सूची सुधारने की यह कवायद लोकतंत्र को मजबूत करेगी या राजनीतिक विवादों को एक नया मोर्चा देगी? मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विपक्ष को आशंका है कि पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के नाम हटने से चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े तर्क हैं कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों, स्थान बदल चुके नागरिकों और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना आवश्यक है। पहली नजर में दोनों पक्षों के तर्क अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। मतदाता सूची का शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन शुद्धता के नाम पर किसी पात्र मतदाता का नाम कट जाना उससे भी गंभीर समस्या है। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच विशेष सारांश पुनरीक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेष गहन पुनरीक्षण और विशेष सारांश पुनरीक्षण, दोनों का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है, लेकिन इनके दायरे और कार्यप्रणाली में अंतर हो सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण में व्यापक स्तर पर मतदाताओं के सत्यापन और सूची की जांच पर जोर दिया जाता है, जबकि विशेष सारांश पुनरीक्षण निध रित कार्यक्रम के तहत नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। ऐसे में विशेष सारांश पुनरीक्षण को विशेष गहन पुनरीक्षण का विकल्प या उसकी काट मान लेना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि इन प्रक्रियाओं के माध्यम से मतदाता सूची को कितना विश्वसनीय बनाया जा रहा है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव तभी है, जब उसमें भाग लेने का अवसर प्रत्येक पात्र नागरिक को मिले। यदि किसी व्यक्ति का नाम तकनीकी गलती, दस्तावेजों की कमी अथवा सत्यापन में हुई चूक के कारण सूची से बाहर हो जाता है, तो उसे अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों, प्रवासी श्रमिकों और दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए ऐसी प्रक्रियाएं अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पलायन और स्थान परिवर्तन बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते समय स्थानीय परिस्थितियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया जितनी सख्त हो, उतनी ही पारदर्शी भी हो। किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन, संबंधित व्यक्ति को सूचना देने की व्यवस्था और आपत्ति दर्ज कराने का वास्तविक अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इसी तरह मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को समयबद्ध राहत मिलनी चाहिए। केवल आंकड़ों में सुधार दिखा देना पर्याप्त नहीं है। सुधार की प्रक्रिया में नागरिकों का भरोसा सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच विशेष सारांश पुनरीक्षण की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह पात्र मतदाताओं को सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने का अवसर दे सकता है। लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता केवल घोषणा से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होगी। कितने पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए, कितने नाम हटाए गए, कितने मामलों में आपत्तियां आईं और कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ, इन सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना जरूरी है। पारदर्शिता ही उन आशंकाओं को दूर कर सकती है, जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर पैदा हुई हैं। निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण और विशेष सारांश पुनरीक्षण के बीच व्यावहारिक संबंध क्या है, पात्र मतदाताओं के लिए कौन-कौन से अवसर उपलब्ध हैं और नाम कटने की स्थिति में शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्या होगी। राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यकर्ताओं को केवल विरोध या आरोप लगाने के बजाय नागरिकों की सहायता के लिए मैदान में उतारना चाहिए। मतदाता सूची की शुद्धता किसी एक दल की जीत या हार का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच विशेष सारांश पुनरीक्षण की दस्तक को न तो राजनीतिक विवाद का अंत माना जा सकता है और न ही अपने आप में किसी नए विवाद का प्रमाण। इसकी कसौटी बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या इससे प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा? क्या किसी का नाम गलत तरीके से हटने पर उसे समय पर न्याय मिलेगा? और क्या पूरी प्रक्रिया राजनीतिक पक्षपात के संदेह से ऊपर उठकर संचालित होगी? लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता केवल मतदान केंद्र पर नहीं, बल्कि मतदाता सूची तैयार होने के समय भी सुनिश्चित होती है। यदि सूची निष्पक्ष है तो चुनावी जनादेश पर भरोसा मजबूत होगा। यदि सूची पर ही सवाल उठने लगे तो चुनाव की विश्वसनीयता प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण हो या विशेष सारांश पुनरीक्षण, प्राथमिकता राजनीतिक दलों का गणित नहीं, नागरिक का मताधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता सूची का हर नाम महत्वपूर्ण है और उस सूची से जुड़ी हर चूक का जवाब भी उतनी ही गंभीरता से दिया जाना चाहिए।

बेटी की हत्या और वीआइपी का सवाल

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली/देहरादून। एक बेटी की हत्या हुई। हत्यारों को सजा मिली, लेकिन उसके माता-पिता के सवाल खत्म नहीं हुए। वह अब भी उस कथित वीआइपी प्रकरण की जांच चाहते हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से विवाद बना हुआ है। न्याय की इसी मांग को लेकर जब अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठे, तो बुधवार रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन गुरुवार तड़के करीब चार बजे दिल्ली पुलिस ने परिवार और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

यह घटनाक्रम कई असहज सवाल छोड़ गया है। क्या किसी पीड़ित परिवार की न्याय की मांग इतनी असुविधाजनक हो गई है कि उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे धरनास्थल से हटा देना आसान समझा जाए? क्या अंकिता के माता-पिता को अपनी बेटी के मामले में उठ रहे सवालों के जवाब पाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक संघर्ष करना पड़ेगा? और क्या संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों से जुड़े विवादों में जांच की निष्पक्षता को लेकर उठने वाली आशंकाओं का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से दिया जा सकता है? सितंबर 2०22 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। मई 2०25 में अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत का फैसला हत्याकांड में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन

अंकिता के परिवार की मौजूदा मांग कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों की जांच को लेकर है। परिवार चाहता है कि इस पहलू की जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। तीन दोषियों को सजा मिलना न्यायिक तथ्य है, जबकि कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े आरोपों की सत्यता जांच का विषय है। दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोपों को खारिज किया है। इसलिए किसी आरोप को

◆अंकिता के परिजनों को आखिर किससे चाहिए न्याय
◆इंडिया गेट पर उठी आवाज को तड़के पुलिस ने रोका
◆दुष्यंत की नियुक्ति पर परिवार के सवालों से घिरी सत्ता

प्रमाणित अपराध मानना उचित नहीं, लेकिन गंभीर सवालों की निष्पक्ष जांच की मांग को भी महज राजनीतिक शोर बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।

दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के विरोध में अंकिता के माता-पिता का दिल्ली पहुंचना इस मामले को नया राजनीतिक आयाम देता है। परिवार की मांग है कि कथित वीआइपी प्रकरण की जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। यह मांग अब केंद्र सरकार के सामने भी राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े कर रही है। संवैधानिक पद पर नियुक्ति अपने आप में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं करती। इसी तरह किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जाने से जांच की आवश्यकता भी समाप्त नहीं हो जाती। यदि कोई गंभीर आरोप जांच के दायरे में है, तो उसका निस्तारण साक्ष्यों

और कानून के आधार पर होना चाहिए। सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव या पद जांच की निष्पक्षता के आड़े नहीं आएगा।

इंडिया गेट पर धरने के दौरान अंकिता के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने की घटना ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार से मिलने के बाद यह मामला राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया। यह सही है कि सार्वजनिक स्थलों पर धरने-प्रदर्शन को लेकर प्रशासन के अपने नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस का दायित्व है। लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब प्रदर्शन करने वाले लोग किसी गंभीर अपराध से जुड़े सवालों पर न्याय की मांग कर रहे हों, तब प्रशासन को कानून का पालन कराने के साथ संवेदनशीलता और पारदर्शिता भी दिखानी चाहिए।

आखिरकार, सवाल यह नहीं कि धरना कहाँ दिया गया। सवाल यह है कि परिवार की मांग पर संबंधित संस्थाओं ने क्या जवाब दिया, जांच की स्थिति क्या है और उठाई गई आपत्तियों का समाधान किस तरह किया जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहा। यह महिला सुरक्षा, राजनीतिक जवाबदेही और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में परिवार का दिल्ली पहुंचना और वहां हिरासत में लिया जाना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा करता है।

►► शेष पृष्ठ 7 पर

केवट लीला और राम-भरत मिलाप ने दर्शकों को किया भावविभोर

हमारे संवाददाता
देहरादून। देहरादून के रेसकोर्स स्थित श्री गुरु नानक मैदान में आयोजित उत्तराखंड की ऐतिहासिक ‘भव्य रामलीला महोत्सव-2026’ का पंचम दिवस ‘हिमालय संरक्षण दिवस’ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल एवं पूर्व विधायक राजकुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रसिद्ध गढ़वाली लोकगायक रोहित चौहान ने अपने भावुक गढ़वाली गीत की शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर दर्शक भावविभोर हो गए।

रामलीला के मंचन में भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी की वनयात्रा के दौरान केवट प्रसंग को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। मंच पर नाव के अद्भुत दृश्य, सरयू नदी की पृष्ठभूमि और आधुनिक तकनीकी प्रभावों ने दर्शकों को ऐसा अनुभव कराया, मानो वे स्वयं उस प्रसंग के साक्षी हों। इसके साथ ही राम-भरत मिलाप के मार्मिक मंचन ने पूरे पंडाल को भावविभोर कर दिया। भाई के प्रति भरत का प्रेम, त्याग और समर्पण दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहा।

समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने



कहा कि हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान, जीवनरेखा और सांस्कृतिक विरासत है। हिमालय का संरक्षण, वनों को बचाना, अधिक से अधिक पौधे लगाना और अपनी लोकसंस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि रामलीला जैसे आयोजन हमारी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और भारतीय परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के साथ-साथ नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना समय की आवश्यकता है और हिमालय की प्राकृतिक धरोहर को

सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला को देहरादून में जीवंत रखना उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का सराहनीय प्रयास है। चंदन सिंह नेगी द्वारा स्थापित ग्रीन बैंक के माध्यम से लोगों की सहभागिता से लाखों पौधे उपलब्ध कराकर पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण को जन-अभियान बनाने के प्रयासों की सराहना की गई। वहीं, रोहित चौहान गढ़वाली लोकगायन के माध्यम से उत्तराखंड की भाषा, लोकधुनों और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने पुरानी टिहरी के डूबने के दर्द का गीत ‘ऐ विधाता मेरी पितरों की बसाई, टिहरी .. गाया। जिसकी लोगों ने भावविभोर होकर सुना

जर्जर भवन की मार, खतरे में पंचायत की चौपाल

उत्तरकाशी(आरएनएस)। धनारी पट्टी के मंजकोट गांव में पंचायत भवन की जर्जर हालत ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भवन की दीवारों पर जगह-जगह दरारें पड़ने से इसके सुरक्षित होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों को न्याय पंचायत की बैठकें करने के लिए इसी भवन का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है। मंजकोट गांव की प्रधान वंदना राणा और अमित राणा ने बताया कि मंजकोट गांव में वर्ष 2००2 में पंचायत भवन का निर्माण किया गया था। लंबे समय से मरम्मत और देखरेख के अभाव में भवन की स्थिति खराब हो गई है। दीवारों पर पड़ी दरारें और भवन की जर्जर हालत किसी संभावित हादसे की आशंका बढ़ा रही हैं। ऐसे में यहां न्याय पंचायत की बैठकें आयोजित करना ग्रामीणों के लिए चुनौती बना हुआ है। कहा कि भवन की खराब स्थिति के संबंध में संबंधित विभाग को कई बार मौखिक और लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद भवन की मरम्मत के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि पंचायत भवन गांव की महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है। न्याय पंचायत की बैठकों सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए भवन का उपयोग किया जाता है लेकिन इसकी जर्जर स्थिति के कारण लोगों को दिक्कतें उठनी पड़ रही हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से पंचायत भवन का निरीक्षण कर उसकी स्थिति का आकलन करने और जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रताप चौहान का कहना है कि सभी विकासखंडों से जर्जर भवनों की रिपोर्ट मांगी गई थी। अगर यह उसमें शामिल होगा। तो इसको जल्द ही ठीक करवाया जाएगा।

भल्डियाणा-कुनेर सड़क पर गड़े ही गड़े, ग्रामीण परेशान

नई टिहरी(आरएनएस)। श्रौलधार ब्लॉक के पांच गांवों को जोड़ने वाली भल्डियाणा-कुनेर सड़क ग्रामीणों के लिए सुविधा के बजाय मुसीबत बन गई है। पिछले 8-1० वर्षों से डामरीकरण और मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हैं। इससे आवागमन मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन सवारों को हो रही है। गड्ढों में टायर फिसलने से उनके चोटिल होने का खतरा बना रहता है।पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पवन रावत ने बताया कि सड़क पर पिछले 8-1० वर्षों से डामरीकरण और मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कुनेर, डांग, भल्डियाणा, ल्वाखा और मझौली गांवों के लोग प्रतिदिन इसी सड़क से आवाजाही करते हैं। ग्रामीण पिछले दो-तीन वर्षों से सड़क की मरम्मत और डामरीकरण की मांग कर रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क मरम्मत के नाम पर गड्ढों में मिट्टी भर दी जाती है। बारिश होते ही मिट्टी बह जाती है और गड्ढे फिर उभर आते हैं। मानकों के अनुरूप सड़क पर मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

पाबौ क्षेत्र को मिली करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात

पौड़ी(आरएनएस)। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पाबौ ब्लॉक के सैंजी, बुरांसी, जगतेश्वर और नौठा क्षेत्र में 16.18 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों को बेहतर आवागमन व शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।विकासखंड पाबौ में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री डॉ. रावत ने बुरांसी मुख्य मार्ग से राईका जगतेश्वर तक 8.21 लाख रुपये की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही करीब 9.37 करोड़ के सात किमी नौठा-बुरांसी-कुल्याणी मोटर मार्ग, 96.13 लाख में सैंजी-कुरगड़खाल से ग्वालखड़ा मोटर मार्ग, राईका जगतेश्वर में 23.8० लाख रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षा कक्ष का शिलान्यास किया। मंत्री ने क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बुरांसी गांव स्थित पातुल्या पौराणिक मंदिर के स्थल विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा तीन लाख रुपये की लागत से प्राचीन बिंदेश्वर मंदिर के स्थल विकास कार्य की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सैंजी-चौलसैंण, जीआईसी व चपलौड़ी-फलदाड़ी सड़क से संबंधित इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं सड़क सुधारीकरण के कार्य भी शामिल हैं।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

भाजपा का चुनावी ‘कमांड सेंटर’ तैयार

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2०27 की लड़ाई को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। काशीपुर में आयोजित विधानसभा विस्तारक एवं विधानसभा प्रभारी कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश सह प्रभारी और मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त विस्तारकों तथा विधानसभा प्रभारियों को चुनावी रणनीति और सांगठनिक प्रबंधन का मार्गदर्शन दिया। अलग-अलग सत्रों में संगठनात्मक ढांचे, राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण देकर इन पदाधिकारियों को चुनावी क्षेत्रों में सक्रिय जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार किया गया।

भाजपा की इस कवायद का राजनीतिक संदेश स्पष्ट है। पार्टी 2०27 के विधानसभा चुनाव को केवल बड़े नेताओं के चेहरे और जनसभाओं के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। उसकी कोशिश चुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था तैयार करने की है, जो स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर रखे, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए और पार्टी की रणनीति को बूथ स्तर तक पहुंचाए। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है। ऐसे में काशीपुर की कार्यशाला को चुनाव से पहले संगठन की मशीनरी को सक्रिय करने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश सह प्रभारी और मुख्यमंत्री की भागीदारी ने संगठनात्मक प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया। अलग-अलग सत्रों में नवनियुक्त विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों को राजनीतिक एवं चुनावी परिस्थितियों को समझने, संगठन की कार्यप्रणाली मजबूत करने और चुनावी जिम्मेदारियों के निर्वहन से जुड़े पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया। भाजपा की रणनीति

चुनावी नहीं, यह राज्य की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा: प्रेमचंद

ऋषिकेश (आरएनएस)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड के लोग आहत हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का मुद्दा राज्य की अस्मिता से जुड़ा है और 2०27 के चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी।रेलवे रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी सेना की एयर और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। सेना के शौर्य पर प्रश्नचिह्न लगाना और पराक्रम के सबूत मांगना उनकी संस्कृति बन गई है।उन्होंने कहा कि देश की सेवा में जुटे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर उत्तराखंड के लोगों को गर्व है। राहुल गांधी की टिप्पणी ने लोगों को अपमानित करने का काम किया है, जिसे राज्य की जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रेसवार्ता में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी, दीपक धमीजा और कौशल बिजल्वान मौजूद रहे।

में संगठन और सरकार के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, स्थानीय समस्याओं की जानकारी जुटाना तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना चुनावी तैयारी के अहम हिस्से हो सकते हैं। हालांकि, इस रणनीति की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण के बाद जमीनी स्तर पर कितना

◆काशीपुर उत्तराखंड में विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों की वलास
◆राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुख्यमंत्री तक ने समझाए सियासी दांव-पेंच
◆अब मैदान में उतरेंगे भाजपा के संगठनात्मक मोर्चे बड़े-बड़े रणनीतिकार

प्रभावी काम होता है।

विधानसभा विस्तारक और प्रभारी भाजपा की चुनावी तैयारी में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। विस्तारकों की भूमिका संगठन की गतिविधियों को गति देने और स्थानीय स्तर पर पार्टी की उपस्थिति मजबूत करने में अहम होगी, जबकि विधानसभा प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक समन्वय और चुनावी तैयारियों की निगरानी करनी होगी। उत्तराखंड में सभी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन, रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के सवाल अहम हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शहरी विकास, बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय राजनीतिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह इन भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करे।

संगठनात्मक प्रशिक्षण के बीच भाजपा के सामने सबसे अहम सवाल जनता की वास्तविक नब्ज पहचानने का होगा। चुनावी रणनीति केवल बैठकों, कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से सफल नहीं होती। इसके लिए यह समझना भी जरूरी है कि मतदाता सरकार के कामकाज को किस नजर से देख रहे हैं और किन मुद्दों पर नाराजगी या समर्थन मौजूद है। बेरोजगारी,

जनगणना-2०27 की तैयारियां तेज, नवंबर से शुरू होगी जनसंख्या गणना

हरिद्वार(आरएनएस)। जनगणना-2०27 के तहत नवंबर से प्रस्तावित जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल फोन के जरिये आंकड़े जुटाएंगे, जबकि कार्य की निगरानी के लिए सीएमएमएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए विकास भवन सभागार में 12 से 14 अक्तूबर तक फील्ड ट्रेनर्स को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर्स आगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक एवं मुख्य प्रमुख जनगणना अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं, नीतियों और भविष्य की आवश्यकताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इससे जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता,

भर्ती प्रक्रिया, भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। विस्तारकों और प्रभारियों के लिए इन सवालों को समझना और संगठन तक वास्तविक फीडबैक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा।

2०27 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर की संभावना के बीच भाजपा की यह तैयारी महत्वपूर्ण है। पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को पहले से सक्रिय कर चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वह भी विधानसभा स्तर पर मजबूत संगठन, प्रभावी नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट रणनीति के साथ मुकाबले में उतरे। हालांकि, संगठनात्मक तैयारियों में तेजी अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। टिकट वितरण, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और जनता का भरोसा भी चुनावी परिणाम तय करेंगे। भाजपा को अपने संगठन की ताकत के साथ इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा।

काशीपुर की कार्यशाला के जरिए नवनियुक्त विधानसभा विस्तारकों और प्रभारियों को चुनावी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब असली परीक्षा उनके क्षेत्रीय कामकाज की होगी।कृवह कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय कर पाते हैं, स्थानीय समस्याओं को संगठन तक कितना प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं और पार्टी की रणनीति को जमीनी स्तर पर कितना लागू कर पाते हैं। भाजपा ने 2०27 की लड़ाई के लिए संगठनात्मक तैयारी का मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री तक का मार्गदर्शन पार्टी की गंभीरता का संकेत देता है। लेकिन चुनावी रणनीति की असली सफलता प्रशिक्षण कक्ष में नहीं, मतदाता के बीच तय होगी। भाजपा के लिए चुनौती केवल चुनावी मशीनरी को सक्रिय करना नहीं, बल्कि उस मशीनरी के जरिए जनता का भरोसा हासिल करना भी है।

पारदर्शिता और तत्परता से निभानी होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रक्रिया में आंकड़ों की शुद्धता और समयबद्ध संकलन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जनगणना से जुड़ी तैयारियां समय से पूरी की जाएं और फील्ड स्तर पर काम करने वाले प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण के साथ तकनीकी जानकारी भी दी जाए। उन्होंने नियमित निगरानी और संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने निदेशक को आश्चस्त किया कि सभी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में जनगणना का कार्य निर्धारित समयसीमा में सटीकता और पारदर्शिता के साथ पूरा कराने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण से लेकर मैदानी स्तर पर कार्य संचालन और निगरानी तक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनकी त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका मुख्य कारण है कि सर्दियों में त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको सर्दियों में त्वचा की देखभाल करते समय नहीं करनी चाहिए।

त्वचा को नमी देना न भूलें : सर्दियां आते ही त्वचा में नमी खोने लगती है और रूखी त्वचा पर जलन और खुजली की समस्या हो सकती है। इसलिए त्वचा को नमी देना न भूलें क्योंकि यह त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप किसी अच्छे नमी देने वाले क्रीम का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि उसमें त्वचा को हाइड्रेट रखने वाले गुण मौजूद हों। इससे आपकी त्वचा कोमल और स्वस्थ बनी रहेगी।

गर्म पानी से न नहाएं : सर्दियों में गर्म पानी से नहाना और हाथ-पैरों को धोना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करने से त्वचा और बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है। इससे त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और अपने हाथ-पैरों को धोने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहाने के बाद त्वचा को नमी देना भी न भूलें।

गर्म कपड़े पहनने से पहले त्वचा पर लगाएं तेल : सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनने से पहले त्वचा को तेल से नमी देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं करना त्वचा के लिए सही नहीं है, खासतौर से पैरों को क्योंकि गर्म कपड़े पहनने के बाद पैरों पर तेल लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है। इसलिए गर्म कपड़े पहनने से पहले पैरों को तेल से नमी जरूर दें।

होंठों की करें देखभाल : सर्दियों में होंठों का फटकर खून निकलने लग जाता है और इस वजह से होंठों की सुंदरता भी खराब हो जाती है। इसलिए होंठों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आप नियमित रूप से अपने होंठों पर शहद और जैतून के तेल को मिलाकर लगाएं या फिर लिप बाम लगाएं। इससे आपके होंठ मुलायम रहेंगे और फटेंगे भी नहीं। यह उपाय आपके होंठों को कोमल बनाए रखेगा।

पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाएं : सर्दियों में कई लोग पर्याप्त पानी पीने की आदत नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी से त्वचा में नमी कम होने लगती है और वह सूखी हो जाती है, इसलिए दिनभर में 7-8 गिलास पानी पीने की आदत डालें। इसके अतिरिक्त आप नींबू पानी, नारियल पानी, ताजे फलों का रस आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी।

सेब बनाम नाशपाती- इनमें से कौन सा फल है अधिक हाइड्रेटिंग ? जानिए

सेब और नाशपाती दोनों ही ऐसे फल हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन अक्सर लोग यह सोचते हैं कि इनमें से किसका सेवन शरीर को अधिक पानी पहुंचाने में मददगार होता है, खासकर गर्मियों में जब शरीर को अधिक पानी की जरूरत होती है। इस लेख में हम इन दोनों फलों की विशेषताओं की तुलना करेंगे ताकि आप सही चयन कर सकें और अपने शरीर को भरपूर पानी दे सकें।

सेब की विशेषताएं : सेब में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो इसे गर्मियों के लिए एक अच्छा फल बनाता है। एक मध्यम आकार का सेब लगभग 85 प्रतिशत पानी से भरा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन-सी, फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सेब का सेवन करने से पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और यह वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नाशपाती भी पानी से भरपूर फल है, जिसमें लगभग 84 प्रतिशत पानी होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन-सी, विटामिन-के और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं। नाशपाती का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर को साफ रखने में मदद मिलती है। इसके फाइबर युक्त गुण पाचन को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिलाते हैं।

सेब और नाशपाती में अंतर : सेब और नाशपाती दोनों में पानी की मात्रा लगभग समान होती है, लेकिन सेब में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में अधिक प्रभावी हो सकता है, वहीं नाशपाती में विटामिन-सी और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होते हैं। दोनों ही फल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

किसका चयन करना चाहिए?

अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसका चयन करना चाहिए?

अगर आप अधिक हाइड्रेशन चाहें तो दोनों ही फल अच्छे विकल्प हैं, लेकिन अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो सेब का चयन करें क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारती है, वहीं अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो नाशपाती बेहतर विकल्प होगा क्योंकि इसमें विटामिन-सी की मात्रा अधिक होती है।

वजन कम करना है ? अपनाएं ये असरदार तरीके

सभी फिट और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन बिगड़ती जीवनशैली के कारण ज्यादातर लोग वजन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। आइये आपको ऐसी टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप वजन कम कर सकेंगे।

गर्म नींबू पानी

नींबू में विटामिन- सी और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।नींबू पानी के सेवन से कमर के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी कम होती है। यह पेय विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक है, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस और थोड़ा-सा शहद मिलाएं, फिर इसका सेवन करें। इसको सुबह खाली पेट पीएं। इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड भी रहेगा।

लीन प्रोटीन

जल्दी वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल करें।ऐसी चीजों के सेवन से वजन घटाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए लीन प्रोटीन के स्रोत अधिक फायदेमंद है।लीन प्रोटीन उन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जिनमें वसा और कैलोरी बहुत कम होती है।इसमें पनीर, क्निनोआ और ग्रीक योगर्ट

बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाएं

छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम होता है। ऐसे में एक अभिभावक होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि, एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, और उसके सही तरीके आपको मालूम होने चाहिए। आमतौर पर अभिभावक पढ़ाई के दौरान अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, ताकि वह डर से पढ़ाई कर सके पर यह तरीका बेहद गलत है, क्योंकि मारने-पीटने से बच्चे और जिद्दी व अड़ियल हो जाते हैं। ऐसे में आपको यह जानना बहुत



जैसी चीजें शामिल हैं।

भोजन पर करें नियंत्रण

गलत खान-पान के कारण भी वजन बढ़ जाता है। ऐसे में भोजन को नियंत्रण में रखना जरूरी है।दरअसल, कभी-कभी हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर कभी कम। इससे बचाव के लिए एक मापने वाले कप का इस्तेमाल करें।इससे आपके भोजन का हिस्सा एक समान होगा, जिससे आपकी डाइट संतुलित बनी रहेगी।इससे यह भी पता चलता है कि आपको एक समय पर कितना भोजना करना है, ताकि आप अधिक कैलोरी न लें।

बंद कर दें मीठे का सेवन

मीठे पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं।जो लोग चीनी और

मीठे पदार्थों का सेवन बंद कर देते हैं, उनका वजन तेजी से कम होता है।कई लोग स्मूदी, सॉफ्ट ड्रिंक या जूस पीते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप मीठे का सेवन करते हैं, जो ठीक नहीं है। इनकी बजाय पूरे फलों का सेवन करें।

स्वस्थ वसा

अगर आप स्वस्थ वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपको तेजी से वजन कम करने में मदद मिलेगी।ये खाद्य पदार्थ प्रोटीन, फाइबर और विटामिन जैसे कुछ पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं।लाभ के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं, जिनमें स्वस्थ वसा की मात्रा ज्यादा होती है। इनमें अलसी के बीज, चिया बीज, मेवे, खासतौर पर अखरोट, और डार्क चॉकलेट शामिल हैं।

शब्द सामर्थ्य -057

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. घुमाव-फिराव वाला, आड़ा-तिरछा, जो कठिन हो 3. कुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता 6. लोग, प्रजा 7. सीता, जनकनंदनी 9. सुंदर, कामना करने योग्य 10. क्रोधपूर्वक बोलने को उद्यत होना, जोश में आना, क्रोधातिरेक में चेहरे का लाल होना 13. अधीनता, मातहतता, वश 14.

दबाव, भार, वजन 16. हृद, मर्यादा 18. प्रमाण-पत्र, प्रमाणिक कथन या बात 19. पछताना (मुहा.) 21. अनुचित मिश्रण, मिलावट 22. विफल, बेहोश, बौखलाया हुआ।

ऊपर से नीचे

1. सहारा, आश्रय, प्रतिज्ञा, संकल्प 2. परिश्रम 4. रात, रात्रि, निशा 5. पुत्र, बेटा 8. मूल्य, दाम 9. कपड़े

का मोटा परदा 11. संदेश भेजना, उच्चारण कराना, कहलवाना 12. मृतकों को जीवित और रोगियों को स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, प्रेमपात्र की संज्ञा 14. देने की क्रिया, खैरात 5. कुमार्गी, दुराचारी 17. मस्तक, माथा, ललाट 18. प्रश्न, समस्या 20. सहायता, सहारा 21. पशुओं को खिलाने वाली हरी पत्तियां, तृण, तिनका।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 56 का हल

ज	द्दो	जे	ह	द		स	पू	त
ल		ब	ल	वा	न			द
म	ह	क		खा	म	खां		बी
ग्न		त	ल	ना		स	फ	र
	म	रा				ना	टा	
	हि		स				फ	न
	ला	ज	वा	ब		म	ट	र
मां		ग		सं	त	ति		भ
	मा	त	ह	त			प	क्षी



तुम मेरे हो का टीजर जारी, फिल्म में दिखेगा गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की प्यार का खूबसूरत सफर

गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की आगामी प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म तुम मेरे हो का गुरुवार को टीजर जारी कर दिया गया। टीजर में दर्शकों को प्यार और भावनाओं से भरी एक ऐसी दुनिया की झलक देखने को मिलती है, जो सामान्य ज़िंदगी से अलग नजर आती है। भावुक क्षणों और खूबसूरत दृश्यों से सजे टीजर में पृष्ठभूमि का संगीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को और गहराई देता है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए ईशा मालवीय हिंदी सिनेमा में अपना पदार्पण करने जा रही हैं। आशीष पांडा के निर्देशन में बनी तुम मेरे हो में गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय के अलावा शान आर. ग़ोवर और अनुष्का लुहार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण आरती एस. और देबिना बनर्जी ने किया है, जबकि रोमांच मेहता और अम्मान रियास्ती सह-निर्माता हैं।

निर्देशक आशीष पांडा ने फिल्म को लेकर कहा कि तुम मेरे हो के जरिए प्यार की गहराई को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करना उनके लिए सपने जैसा है। उनके अनुसार, यह केवल खूबसूरत प्रेम क्षणों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें उन भावनाओं, चुनौतियों और परिस्थितियों को भी दिखाया गया है, जो दो लोगों के रिश्ते की परीक्षा लेती हैं।

उन्होंने कहा कि फिल्म में गहरी प्रेम कहानी के साथ कार्रवाई और रोमांच का भी समावेश किया गया है। इसका उद्देश्य दर्शकों को बड़े स्तर का सिनेमाई अनुभव देना है। गुरमीत चौधरी के साथ काम करने के अनुभव पर आशीष पांडा ने कहा कि अभिनेता और निर्माता के रूप में उनके साथ काम करना बेहद सहज रहा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि टीम केवल एक फिल्म बना रही है, बल्कि लगा कि सभी मिलकर दिल से निकली कोई कहानी तैयार कर रहे हैं। निर्देशक के मुताबिक, गुरमीत ने अपने किरदार के लिए ज़रूरी गंभीरता और विश्वास को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया तथा वह पूरी तरह फिल्म की दुनिया में डूब गए। फिल्म की कहानी निरंजन अयंगर और पूर्वा नरेश ने लिखी है। इसके गीत रश्मि विराग मिश्रा, मिथुन, अजीम शिराजी, संजू राठौड़, विवेक वर्मा और गीत सागर ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत मिथुन, संजू राठौड़, विवेक वर्मा, कृष, उद्दीपन शर्मा और अर्जुन हरजाई ने तैयार किया है। तुम मेरे हो इसी वर्ष 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

नानी की ब्लडी रोमियो में मचेगा धमाल, मुख्य भूमिका में नजर आएगी अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन

अभिनेता नानी अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म द पैराडाइज की सफलता के बाद अब एक नई फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने की तैयारी में हैं। नानी आगामी फिल्म ब्लडी रोमियो में निर्देशक सुजीत के साथ काम करेंगे। फिल्म को लेकर निर्माताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इस फिल्म में अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में यह फिल्म उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फिल्म में नानी और प्रीति मुकुंदन की जोड़ी पहली बार दर्शकों के सामने नजर आएगी।

ब्लडी रोमियो में एक्शन, हास्य और आकर्षक अंदाज का मिश्रण देखने को मिलेगा। निर्माताओं के अनुसार, फिल्म की कहानी और नानी का किरदार दर्शकों के लिए कुछ नया पेश करने की कोशिश करेगा। नानी अपने किरदार को प्रभावी बनाने के लिए शारीरिक रूप से भी खुद को तैयार कर रहे हैं और उनके रूप-रंग में बदलाव देखने को मिल सकता है।

फिल्म की शूटिंग लंदन, दिल्ली और हैदराबाद सहित अलग-अलग स्थानों पर किए जाने की योजना है। फिल्म का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। निर्माताओं ने संकेत दिया है कि परियोजना आगे बढ़ने के साथ फिल्म के अन्य कलाकारों से जुड़ी जानकारी भी साझा की जाएगी।

ब्लडी रोमियो की वर्ष 2027 की गर्मियों के बाद सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखा गया है। द पैराडाइज की सफलता के बाद नानी की इस नई फिल्म को लेकर उनके प्रशंसकों में अभी से उत्सुकता बनी हुई है।

भाषा से भावना व्यक्त करने के तरीके में बदलाव आता है : मालवी मल्होत्रा

लुगु क्राइम-कॉमेडी फिल्म बा बा ब्लैक शीप में अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा रमा के किरदार में नजर आ रही हैं। साउथ इंडस्ट्री में काम करने पर अभिनेत्री ने कहा कि भाषा इस बात को भी दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करते हैं। अभिनेत्री ने कहा, हर इंडस्ट्री की काम करने की संस्कृति, लय और कहानी कहने की भाषा होती है और मेरे लिए इससे परिचित होना मददगार है। भाषा सिर्फ शब्दों या उच्चारण के बारे में नहीं है बल्कि, यह दिखाती है कि आप अपने मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, सीन की लय कैसी होती है और आप अपने सह-कलाकार को कैसे सुनते हैं। आखिरकार, भावनाएं सार्वभौमिक होती हैं। चाहे आप हिंदी, तेलुगु, तमिल या मलयालम बोल रहे हों, किरदार की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस समझ ने मुझे और अधिक सहज और बहुमुखी कलाकार बना दिया है। अभिनेत्री ने रमा के किरदार के बारे में बताते हुए कहा, रमा की अपनी अलग पहचान और इमोशनल सफर है। मुझे यह पसंद आया कि उसे सिर्फ हीरो के आसपास या उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। उसके कई पहलू हैं और जहां कुछ पहलू वास्तविकता के करीब थे, वहीं कुछ ने मुझे अपने व्यक्तित्व से बाहर ला दिया। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह था उसे एक असली इंसान जैसा महसूस कराने का अवसर, जिसमें उसके अपने विचार, कमजोरियां और ताकतें हों।

अपनी भूमिका की तैयारी के बारे में बताते हुए मालवी ने कहा, मैं आमतौर पर

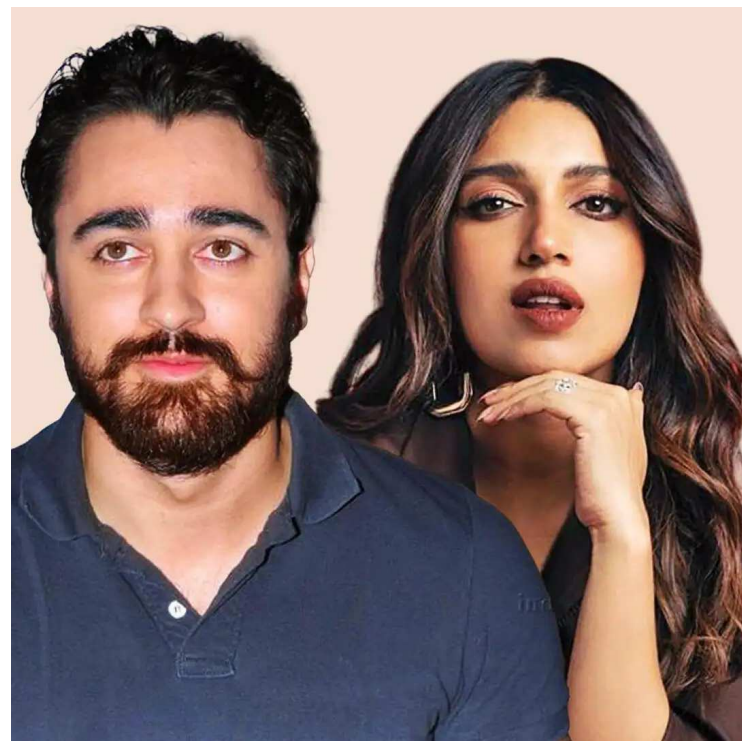


किरदार के बारे में ज्यादा कुछ तय नहीं करती, जब तक कि मैं यह न समझ लूं कि वह किस दुनिया से आती है, क्या चाहती है, किससे डरती है और किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। मैंने स्पष्ट हावभाव बनाने के बजाय अपने अभिनय को सहज बनाने की कोशिश की थी। मेरी थिएटर ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया है कि छोटी-छोटी बातें किसी किरदार को विश्वसनीय बना सकती हैं, इसलिए मैंने उसके आंतरिक जीवन पर अधिक ध्यान दिया और हावभाव को

स्वाभाविक रूप से उभरने दिया।

उन्होंने कहा, मुझे तुरंत जिस चीज ने आकर्षित किया था, वह कहानी और उसकी दुनिया थी। मैं ऐसे प्रोजेक्ट खोजती हूं, जहां पात्रों की अपनी यात्राएं हों और कुछ सार्थक योगदान हो। जब मैंने पटकथा पढ़ी, तो मुझे लगा कि पात्र और उनकी भावनाएं कहानी को चला रही हैं। मैं सिर्फ पैमाने या ग्लैमर के कारण किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से ज्यादा अच्छी कहानी का हिस्सा बनना पसंद करती हूं।

भूमि पेडनेकर के साथ शानदार वापसी करेंगे इमरान खान, साल के अंत में होगा धमाका



अभिनेता इमरान खान सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद अब एक शानदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी नई फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम 2026 की शुरुआत में रिलीज होने वाली

थी, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में रहने वाली हैं। हालांकि, अभिनेता ने खुलासा किया है कि ये फिल्म अब दिसंबर में क्रिसमस के आसपास रिलीज हो सकती है। इमरान की इस फिल्म

का उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इमरान खान ने बताया, हमें जानकारी मिली है कि निर्माता इसे 18 दिसंबर के आसपास रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए हम पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से निपटा रहे हैं ताकि समय पर फिल्म सौंप सकें। चूंकि ये फिल्म सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, इसलिए तारीख से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आखिरकार हम यह फिल्म दर्शकों के सामने ला पा रहे हैं।

अधूरे हम अधूरे तुम से इमरान करीब 11 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इससे पहले उन्हें 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म कट्टी-बट्टी में देखा गया था।

इस नई फिल्म के जरिए इमरान 2010 में आई ब्रेक के बाद के बाद एक बार फिर निर्देशक दानिश असलम के साथ काम कर रहे हैं। अभिनेता मानते हैं, यह वो फिल्म है, जिसे हमें 16 साल बाद बनाना ही चाहिए था।

मानसखण्ड विज्ञान केंद्र में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल, विद्यार्थियों को सिखाए बचाव के तरीके

अल्मोड़ा (आरएनएस)। मानसखण्ड विज्ञान केंद्र, अल्मोड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), सिमार, बागेश्वर से आए विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अग्निशमन दल ने आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों और आपातकाल में सुरक्षित निकासी की जानकारी दी। मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि आग लगने पर घबराने के बजाय सतर्कता बरतते हुए भवन को सुरक्षित तरीके से खाली करना चाहिए। साथ ही आग में घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और प्राथमिक बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। अग्निशमन दल ने विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के उपयोग और आग बुझाने की सही विधि समझाई। इसके बाद यंत्रों के इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से स्ट्रेचर बनाने की विधि भी प्रदर्शित की गई। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आपदा के समय सावधानी, सूझबूझ और आपसी सहयोग का महत्व बताया गया। कार्यक्रम में फायर ऑफिसर ओम प्रकाश, डॉ. प्रियंका अधिकारी, हरि सिंह अधिकारी, नीरज कुमार, मनीषा गोस्वामी, इंद्रावती, पूजा थापा, आकांक्षा डसीला सहित अग्निशमन दल के अन्य कार्मिक मौजूद रहे।

बैंक मित्रों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश

रुद्रपुर (आरएनएस)। भारतीय स्टेट बैंक के जिलेभर के बैंक मित्रों की बैठक रुद्रपुर स्थित क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक शरद खंडेलवाल ने की। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को इनसे जोड़ने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक शरद खंडेलवाल ने कहा कि बैंक मित्र ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके माध्यम से आम लोगों तक केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सभी बैंक मित्र जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें। बैठक में मौजूद बैंक मित्रों ने समय पर लक्ष्य पूरा करने और योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रियता से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। यहां प्रबंधक वित्तीय समावेशन महिमन सिंह, सहायक प्रबंधक अर्पित नेगी, बीएलएस जीरो मास कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर नरेश शर्मा, स्टारफिन से फैजान अली, संजीवनी से विकी दास सहित सीएसपी संचालक रामदुलाल चक्रवर्ती, राकेश कुमार, अशोक कुमार, सूरज मंडल, रमेश चंद, गौरव जोशी, मनीष डोगरा, अनिल कुमार, सुरेंद्र सिंह, पूजा रानी, प्रियंका आर्य, ईशा, ज्योति दास, ममता पंत रहीं।

सू- दोकू क्र.057

9		8		1		7		
4		6			7		5	
	3			6		8		9
		3			1		6	
5			6			9		
		9		5			3	
3			7		9			1
	5			2		3	9	
1		4			8		7	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.56 का हल

7	5	6	4	1	2	8	3	9
3	4	8	6	7	9	2	1	5
1	2	9	5	3	8	7	4	6
2	8	1	9	5	6	4	7	3
6	9	7	2	4	3	5	8	1
5	3	4	7	8	1	9	6	2
8	7	2	1	6	5	3	9	4
4	6	5	3	9	7	1	2	8
9	1	3	8	2	4	6	5	7

2027 के रण के लिए ‘चक्रव्यूह’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात पर भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग का समापन सत्र पार्टी की इसी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा का जोर अब केवल राजनीतिक संदेशों और बड़े नेताओं की सभाओं तक सीमित रहने के बजाय संगठन की जमीनी ताकत को चुनावी नतीजों में बदलने पर है। विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति के प्रमुख आधार बन सकते हैं।

भाजपा के लिए उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती आसान नहीं है। पार्टी जहां अपने संगठनात्मक ढांचे, केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को चुनावी ताकत बनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों का प्रशिक्षण केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा की चुनावी रणनीति में बूथ प्रबंधन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पार्टी का मानना है कि चुनावी सफलता के लिए प्रदेश नेतृत्व की रणनीति तभी कारगर होगी, जब उसका क्रियान्वयन विधानसभा और बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से हो। विस्तारकों

की भूमिका इसी कड़ी में अहम हो जाती है। उन्हें संगठन की गतिविधियों को गति देने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने और जमीनी राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाने जैसे दायित्व निभाने होते

◆विधानसभा प्रभारी और विस्तारकों की मैदान में उतारने की तैयारी
◆बूथ से विधानसभा तक पकड़ मजबूत करने की रणनीति हुई तय
◆उत्तराखंड में तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती नहीं आसान

हैं। विधानसभा प्रभारियों के सामने भी बड़ी चुनौती है। उन्हें स्थानीय संगठन, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और संभावित चुनावी मुद्दों के बीच समन्वय बनाना होगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं, पलायन, रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मैदानी क्षेत्रों की अलग राजनीतिक चुनौतियां चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती हैं, वहां एक जैसी रणनीति हर विधानसभा में कारगर नहीं हो सकती।

उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं और भाजपा के सामने हर सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती है। पार्टी नेतृत्व के सामने लक्ष्य केवल सत्ता में वापसी करना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी संगठन को मजबूत करना है जहां विपक्षी दलों की पकड़ रही है या स्थानीय असंतोष चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है। विस्तारक योजना को इसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। संगठन की जमीनी रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं के बीच सरकार की छवि का आकलन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, प्रशिक्षण और संगठनात्मक

बैठकों का वास्तविक परिणाम इस बात से तय होगा कि उनके बाद जमीन पर कितना बदलाव दिखाई देता है।

भाजपा की संगठनात्मक सक्रियता कांग्रेस के लिए भी चुनौती पैदा कर सकती है। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, कथित भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं जैसे मुद्दों को धार देने की कोशिश कर सकती है, वहीं भाजपा अपने संगठन के माध्यम से सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संदेशों को घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति अपना सकती है। लेकिन केवल संगठनात्मक मजबूती चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। स्थानीय नाराजगी, टिकट वितरण, नेताओं के बीच तालमेल और सरकार के प्रति जनता की धारणा भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि संगठन की ताकत को जनता के समर्थन में कितना बदला जा सकता है।

विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग का समापन सत्र भाजपा की चुनावी तैयारी के अगले चरण का संकेत है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रशिक्षण के दौरान तय रणनीति को किस तरह लागू किया जाता है और विधानसभा स्तर पर संगठन कितनी सक्रियता दिखाता है। भाजपा का लक्ष्य साफ है कि चुनाव से पहले संगठन को चुस्त करना, बूथ तक पहुंच मजबूत करना और हर विधानसभा में राजनीतिक स्थिति पर नजर रखना। लेकिन 2027 की लड़ाई में संगठनात्मक अनुशासन के साथ जनविश्वास भी उतना ही जरूरी होगा। चुनावी मशीनरी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अंतिम फैसला मतदाता ही करेगा।

सत्ता में वापसी के दावे ‘ख्याली पुलाव’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जुबानी जंग तेज होने लगी है। कांग्रेस के सत्ता में वापसी के दावों पर भाजपा ने तीखा पलटवार करते हुए इन्हें ख्याली पुलाव करार दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भले ही सत्ता में लौटने के सपने देख रही हो, लेकिन प्रदेश की जनता उसे ऐसी कोई दावत देने के मूड में नहीं है। भाजपा के इस हमले ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल जनसभाओं और संगठनात्मक तैयारियों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि राजनीतिक दावों और जवाबी हमलों के बीच भी सियासी तापमान बढ़ेगा। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाकर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है, वहीं भाजपा विपक्ष के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताकर उसकी चुनावी संभावनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।

भाजपा के निशाने पर कांग्रेस की वह राजनीतिक उम्मीद है, जिसके सहारे पार्टी 2027 में सत्ता परिवर्तन की संभावना जता रही है। भाजपा का तंज है कि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले ही जीत की दावत सजाने लगे हैं, जबकि जनता ने अभी उन्हें सत्ता की थाली परोसने का कोई संकेत

नहीं दिया है। भाजपा इस बयान के जरिए कांग्रेस के आत्मविश्वास को अतिआत्मविश्वास साबित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का संदेश है कि चुनावी जीत के दावे करना और मतदाताओं का समर्थन हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई लंबे

◆भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जुबानी जंग
◆कांग्रेस को सत्ता की दावत देने के मूड में नहीं जनता
◆2027 में भी नहीं पूरी होगी कांग्रेस पार्टी की हसरत

समय से प्रमुख चुनावी धुरी रही है। 2027 के चुनाव से पहले दोनों दल अपनी-अपनी जीत का माहौल बनाने में जुटे हैं। भाजपा संगठनात्मक तैयारियों और सरकार के कामकाज को अपनी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन असंतोष को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर सकती है।

ऐसे में ख्याली पुलाव वाला हमला केवल राजनीतिक कटाक्ष नहीं, बल्कि विपक्ष के चुनावी आत्मविश्वास को चुनौती देने की रणनीति भी है। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने के दावों को

जनता के बीच समय से पहले की गई राजनीतिक घोषणा के रूप में देखा जाए। कांग्रेस के दावों पर भाजपा का हमला अपनी जगह है, लेकिन 2027 की चुनावी तस्वीर केवल बयानों से तय नहीं होगी। बेरोजगारी, भर्ती, पलायन, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाएं और सरकार के प्रति जनता की धारणा जैसे मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा के लिए चुनौती अपने संगठनात्मक आधार को बनाए रखने और सरकार के कामकाज के प्रति जनता का भरोसा कायम रखने की होगी। वहीं, कांग्रेस के सामने अपनी एकजुटता, नेतृत्व और जमीनी संगठन को मजबूत कर सत्ता में वापसी के दावों को विश्वसनीय बनाने की चुनौती है।

फिलहाल भाजपा ने कांग्रेस के सत्ता में लौटने के दावों को खारिज करते हुए राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र में न सत्तारूढ़ दल का आत्मविश्वास जीत की गारंटी है और न विपक्ष का दावा सत्ता तक पहुंचने का प्रमाण। 2027 में किसकी दावत सजेगी और किसके हिस्से इंतजार आएगा, इसका फैसला भाजपा के तंज या कांग्रेस के दावों से नहीं, उत्तराखंड की जनता के वोट से होगा। फिलहाल चुनाव से पहले ही सियासी रसोई गर्म है और दोनों दल अपनी-अपनी जीत का पकवान तैयार करने में जुटे हैं।

उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार हो राज्य का स्किल डेवलपमेंट प्लान: मुख्य सचिव

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग एवं इंडस्ट्री सहित प्राईवेट प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश का स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य एवं जनपद स्तर पर कौशल विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों की डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान शीघ्र तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपदों में रोजगार की संभावनाओं, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं तथा कौशल की मांग का आंकलन करते हुए योजना तैयार किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन उनके अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता और प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के बीच के अंतर को चिह्नित कर उसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार अवसरों और प्रशिक्षण के लक्ष्यों का आंकलन करते हुए योजना तैयार की जाए। उन्होंने उभरते हुए कौशल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने तथा इस सम्बन्ध में सेतु आयोग के अध्ययन का भी उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने पर जोर देते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ तथा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानक निर्धारित किए जाएं, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में एकरूपता लाई जा सके।

महिला मंत्री ने लगाई सुरक्षा की गुहार.. << पृष्ठ 1 का शेष

होनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले की जांच राजनीतिक दबाव या सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से प्रभावित न हो। कानून की नजर में हर नागरिक समान है और किसी भी शिकायत का निस्तारण साक्ष्यों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।

रेखा आर्य के आरोपों से भाजपा सरकार के सामने भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है। महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों तथा दावों पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। विपक्ष इस प्रकरण को सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। यदि शिकायत में सुरक्षा संबंधी वास्तविक खतरे की बात कही गई है, तो पहली प्राथमिकता मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना होना चाहिए। इसके बाद ही तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

रेखा आर्य के भावुक वीडियो, थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी के बाद अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं। क्या मंत्री की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं का आकलन किया गया है? क्या शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है? कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की जांच में क्या सामने आया है? इन सवालों का जवाब मामले की आगे की दिशा तय करेगा। फिलहाल, यह प्रकरण केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह गया है। इसने महिला सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही सरकार और पुलिस दोनों के लिए सवाल खड़े कर सकती है।

बेटी की हत्या और वीआइपी का.. << पृष्ठ 2 का शेष

भाजपा सरकार अपनी पुलिस कार्रवाई, जांच और अदालत से मिली सजा का हवाला दे सकती है। लेकिन परिवार की वर्तमान मांग का जवाब केवल यह बताकर नहीं दिया जा सकता कि दोषियों को सजा मिल चुकी है। यदि परिवार कथित वीआइपी प्रकरण को लेकर अलग सवाल उठा रहा है, तो उन सवालों की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए भी यह मामला केवल सरकार को घेरने का अवसर नहीं होना चाहिए। यदि विपक्ष वास्तव में अंकिता को न्याय दिलाने के पक्ष में है, तो उसे आरोपों की निष्पक्ष जांच और परिवार की मांगों के समाधान पर लगातार जोर देना होगा। न्याय का प्रश्न किसी एक दल की राजनीतिक सुविधा से बड़ा है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता का परिवार है। बेटी खो चुके माता-पिता जब बार-बार सार्वजनिक रूप से न्याय की मांग कर रहे हों, तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुने और तथ्यों के आधार पर जवाब दे। परिवार ने हिरासत से छूटने के बाद सरकार को 24 घंटे का समय देने और मांग पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह चेतावनी बताती है कि मामला केवल एक दिन के धरने तक सीमित रहने वाला नहीं है। यदि परिवार की आशंकाओं का समाधान नहीं हुआ, तो उत्तराखंड की राजनीति में यह मुद्दा फिर जोर पकड़ सकता है। सरकार के लिए बेहतर रास्ता यही होगा कि आरोपों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय जांच की स्थिति स्पष्ट करे और परिवार को भरोसे में लेने के लिए ठोस कदम उठाए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने को दी मंजूरी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या वर्तमान 526 से बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या वर्तमान 526 से बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके तहत 1474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों एवं शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के तथा कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना, वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का पृथक प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त पर सहमति व्यक्त की

शहरी स्थानीय निकायों एवं सीसी मार्ग निर्माण हेतु 400.9 करोड़ रुपये स्वीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय किश्त (अक्टूबर से दिसंबर, 2026) के लिए 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय छमाही किश्त (अक्टूबर 2026 से मार्च 2027) के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल 3 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 72.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस सीसी मार्ग निर्माण कार्य के लिए 60 प्रतिशत की दर से 43.578 लाख की प्रथम किश्त स्वीकृत करते हुए शासनादेश जारी किया गया।

गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन तथा उनके लिए भविष्य में पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने की दिशा में

भी पहल की जाएगी। प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत लक्ष्मण सिद्ध मंदिर परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान



संवाददाता

देहरादून। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत हरवाला स्थित लक्ष्मण सिद्ध मंदिर परिसर एवं आसपास के वन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में हरवाला के पार्षद, नगर निगम देहरादून की टीम, वन विभाग की टीम तथा वेस्ट वॉरियर्स संस्था ने संयुक्त रूप से सहभागिता की। सभी ने श्रमदान

कर मंदिर परिसर एवं वन क्षेत्र से प्लास्टिक सहित अन्य कचरा एकत्रित किया। अभियान के दौरान एकत्रित प्लास्टिक कचरे को उचित प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के लिए वेस्ट वॉरियर्स संस्था के स्वच्छता केंद्र भेजा गया।

वेस्ट वॉरियर्स संस्था के सहायक निदेशक नवीन कुमार सडाना ने बताया कि धार्मिक स्थलों एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक

जिम्मेदारी है। संस्था द्वारा लक्ष्मण सिद्ध मंदिर परिसर में पहले से ही कचरे के उचित संग्रहण के लिए चार डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को स्थायी बनाने के लिए केवल सफाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कचरा फैलने से रोकना और उसका उचित प्रबंधन करना भी जरूरी है।

अभियान में स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम देहरादून के ब्रांड एंबेसडर भारत शर्मा, रजत, मनीष, अमित, जसप्रीत, नीरज, विशाल सहित नगर निगम, वेस्ट वॉरियर्स संस्था, वन विभाग, स्थानीय नागरिक एवं सारथी संस्था के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों से अपील की गई कि वे धार्मिक स्थलों की पवित्रता, वन क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने में अपना योगदान दें।

नवरात्रि पर कीर्तन मंडलियों को भेंट की गई कीर्तन किट

हमारे संवाददाता

देहरादून। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में नवरात्रि के शुभ अवसर पर 11 हजार कन्या पूजन का लक्ष्य, को पूरा करते हुए पांचवें नवरात्रि स्कंदमाता की पूजा अर्चना कर, नवरात्रि पर कीर्तन मंडलियों को कीर्तन किट भेंट की गई।

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां स्कंदमाता की आराधना, नारी शक्ति के सम्मान और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य अध्यक्ष जी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नवरात्रि के पंचम दिवस पर वार्ड संख्या 44, पटेल नगर पश्चिम, सरदार पटेल मंडल के अंतर्गत 21 कैंट विधानसभा क्षेत्र स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि बस्ती, देहरादून में सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग



के अध्यक्ष एवं भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधि-विधान से कन्याओं का पूजन कर मां स्कंदमाता की आराधना की गई तथा क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की गई।

इसी क्रम में वार्ड संख्या 38, पंडितवाड़ी स्थित स्वामी विवेकानंद मंडल में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में भी सहभागिता की गई। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि

शारदीय नवरात्रि हमारी आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण पर्व है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समाज में बेटियों के महत्व को स्वीकार करने का प्रतीक है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने और भजन-कीर्तन के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने वाली कीर्तन मंडलियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कीर्तन किट वितरित की गई।

दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने के विरोध में विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन



संवाददाता

देहरादून। अंकिता भण्डारी हत्याकांड में वीआईपी का आरोप लगने के बाद दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाये जाने के विरोध में विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस से दुपहिया रैली निकाली।

आज यहां विभिन्न संगठनों के लोग गांधी पार्क में एकत्रित हुए। जहां पर उन्होंने अंकिता भण्डारी हत्याकांड के वीवीआईपी का आरोप लगने के बाद दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाये जाने पर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा की केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि इतने बड़े हत्याकाण्ड के कथित वीवीआईपी

दुष्यंत गौतम को केन्द्र सरकार ने सिक्किम का राज्यपाल बना दिया जिसके कारण अंकिता भण्डारी की हत्या को अंजाम दिया गया था। वहीं अंकिता के माता-पिता को केन्द्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से घसीटते हुए ले

कांग्रेस ने निकाली दुपहिया रैली

जाने पर लोगों ने तीखी आलौचना की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी घंटाघर स्थित उत्तराखण्ड के गांधी इन्द्रमणि बडोनी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए जहां से उन्होंने दुष्यंत गौतम व भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुपहिया वाहन रैली निकाली।

रैली शहर की विभिन्न सड़कों से होते शिमला बाईपास से वापस घंटाघर के लिए निकली।

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध सरकार की नाकामी को साबित करते हैं। प्रदेश सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हुई है। वहीं दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाये जाने पर खेद प्रकट किया और इसको केन्द्र सरकार की हठधर्मिता कहा गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलेजा, प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धरमाना, लालचंद शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने दो अग्निवीरों के 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजन को दी मंजूरी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के पहले बैच के दो अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया था कि भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने जा रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के दो अग्निवीरों के समायोजन की अपेक्षा की गई थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष दो अग्निवीरों के समायोजन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को



आगे भी सेवा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई अग्निपथ योजना देश के युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को सशक्त कर रही है। अग्निवीर भारतीय सेना में सेवा के दौरान जो कौशल, अनुभव और अनुशासन अर्जित करते हैं, वह राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है। हमारी सरकार अग्निवीरों के योगदान और उनकी क्षमताओं का सम्मान करती है। हमारा प्रयास है कि देश की सेवा कर चुके इन युवाओं को आगे भी प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिले और उनके सैन्य अनुभव, अनुशासन एवं दक्षता का लाभ राज्य को प्राप्त हो। उत्तराखंड सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रसेवा के उनके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोक भवन के मुख्य गेट को खोलने का प्रयास करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित 30 पर मुकदमा

संवाददाता

देहरादून। लोक भवन के मुख्य गेट को खोलने का प्रयास करने पर पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैप्टन कोतवाल संतोष सिंह कुंवर ने कैप्टन कोतवाली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, गरिमा दसोनी, ज्योति रौतेला, हरीश रावत, राजकुमार, लालचन्द शर्मा, आशा मनोरमा शर्मा, विनोद चौहान, मोहन कुमार काला,



सूरज क्षेत्री, गोदावरी थापली, स्वाती नेगी, मनीष गोनियाल, डॉ. प्रतीमा सिंह, राजेन्द्र शाह, अवशनी बहुगुणा, पीयूष जोशी, ललित भद्री, चन्द्र कला नेगी, गुल मौहम्मद, गोपाल सिंह गडिया, रितेश क्षेत्री, सुरेन्द्र सिंह रांगड, सुनीता सिंह राठौर, हरि कृष्ण भट्ट, दीपक मधवाल, पुष्पा पंवार व अन्य के खिलाफ एक राय होकर बिना कोई वैध अनुमति प्राप्त किये लोक भवन तक पहुंचकर पुलिस कर्मियों द्वारा दिये गये विधि वत निर्देशों की अहंवेला करते हुए बैरिकेडिंग पार करना तथा लोक भवन के मुख्य गेट को खोलने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

टेस्ला ने लॉन्च की उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार!

संवाददाता

नई दिल्ली। दुनिया के प्रमुख उद्योगपति एलन मस्क ने टेस्ला की दूसरी पीढ़ी की नई रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स से जुड़े थ्रस्टर्स की मदद से कार को हवा में उठाने और घुमाने का प्रदर्शन किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार चार्ज करने पर करीब 483 किलोमीटर चल सकती है। इसके तीन वेरिएंट होंगे और उत्पादन 2028 में शुरू करने की योजना है, लेकिन इस कार की बुकिंग के लिए कितनी रकम जमा करनी होगी और इसके उड़ने वाले फीचर के साथ सुरक्षा को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं?

टेक्सास के वाको के पास आयोजित



एक इवेंट में इस कार का प्रदर्शन किया गया। यहां रोडस्टर ने हाई-पावर वाले पंखों और थ्रस्टर्स की मदद से एक उल्टे रैंप पर चढ़ाई की, हवा में घूमि और फिर जमीन पर सुरक्षित उतर गई। इसके अलावा, चलते हुए कार को थ्रस्टर्स की मदद से साइबरकैब, साइबरट्रक, टेस्ला सेमी, मॉडल वाई और मॉडल 3 के ऊपर से गुजरते

हुए भी दिखाया गया। मस्क ने कहा, यही वह असली कार होगी जो सड़कों पर चलेगी। उनके अनुसार, कार जरूरत पड़ने पर खुद को ऊपर उठा सकती है और ऐसे करतब दिखा सकती है। टेस्ला ने इसका उत्पादन 2028 में शुरू करने की बात कही है, हालांकि कार की पूरी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

पूजा करने आया व्यक्ति नदी में डूबा!

हमारे संवाददाता

टिहरी। देवप्रयाग संगम से थोड़ा आगे दूधप्रयाग में आज सुबह पूजा का दिन मातम में बदल गया। नहाते वक्त पैर फिसला और एक व्यक्ति देखते ही देखते गहरी नदी में समा गया।

बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने गांव के कई लोगों के साथ पूजा के लिए दूधप्रयाग पहुंचा था। सभी लोग नदी किनारे पूजा की तैयारी में थे, तभी वह नहाने के लिए पानी में उतरा। अचानक संतुलन बिगड़ा और तेज बहाव उसे बहा ले गया। साथ आए लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वह आंखों से ओझल हो गया। घटना की सूचना तुरंत कीर्तिनगर थाने को दी गई। प्रभारी



निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में डूबा व्यक्ति डागर जाखी क्षेत्र का रहने वाला है।

सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ हरकत में आ गई।

एसडीआरएफ के मुताबिक आज सुबह 11:17 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी। सब इंस्पेक्टर कुलदीपक पांडेय के नेतृत्व में टीम तुरंत रवाना हुई। हेड कांस्टेबल विवेकानंद, सुमित तोमर, विकास

रावत, प्रवीण राव समेत पूरी टीम नदी और आसपास के किनारों पर लगातार सर्च कर रही है। समाचार लिखे जाने तक व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है, रेस्क्यू अभियान जारी है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।